दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 18 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 258

महत्वपूर्ण एवं खास

जुलाई में आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में अभी 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब उम्मीद बढ़ी है कि अगले कुछ महीनों में बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी और उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई में कोरोना की वैक्सीन नोवावैक्स का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करेगी। अमेरिकी बायोटेक्नॉलजी कंपनी नोवावैक्स ने पिछले साल सितंबर में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन बनवाने का समझौता किया था। नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन भारत में कोवोवैक्स के नाम से बनेगी। सितंबर तक सीरम इस वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। भारत में उसका ब्रीजिंग ट्रायल अंतिम दौर में है। हालांकि, बच्चों पर इसका अलग से क्लीनिकल ट्रायल होगा और उसमें सबकुछ ठीक होने के बाद ही यह बच्चों के लिए उपलब्ध होगी।

कोरोना वायरस के सभी वैरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी 2-डीजी

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित कोरोना वायरस की दवा 2-डियोक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी), कोविड-19 के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रभावी है और यहां तक कि यह दवा सार्स-सीओवी-2 वायरस के मल्टीप्लिकेशन को भी कम करती है। प्रारंभिक अध्ययन से यह भी पता चला है कि डीआरडीओ की एंटी-कोविड दवा कोशिकाओं में संक्रमण से प्रेरित साइटोपैथिक प्रभाव (सीपीई) को कम करती है और उन्हें खत्म होने से बचाती है। गौरतलब है कि 2-डीजी दवा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में 17 मई को लॉन्च किया था। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा की पहली खेप जारी करते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया कि इस दवा में मरीज के ठीक होने में लगने वाले औसत समय को ढाई दिन और ऑक्सीजन की मांग को 40 फीसदी तक कम करने की क्षमता है। इसे भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा एक जून को मध्यम से गंभीर कोरोना वायरस मरीजों के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकरण प्रदान किया गया था।

फरीदाबाद में 10 हजार मकानों पर चलेगा बुलडोजर

❐ **सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर रोक से इनकार**

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित करीब 10 हजार घरों को छह हफ्ते के भीतर ढहाने का अपने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि हमारी राय में इस चरण पर न्यायालय द्वारा दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ढहाने की कार्रवाई न की जाए। वहां अधिकतर प्रवासी मजदूर रहते है और संकट के इस दौर में वे बेघर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निगम, पुनर्वास योजना के लिए यहां रहने वाले लोगों के दस्तावेजो को स्वीकार नहीं कर रहा है। जवाब में पीठ ने कहा कि ढहाने की कार्यवाही को हम नहीं रोक सकते। लोगों के पास वन भूमि खाली करने का पर्याप्त अवसर था। पिछले छह सालों से यह सब कुछ चल रहा है। वही पुनर्वास योजना के लिए दस्तावेजों को स्वीकार न करने के आरोप पर पीठ ने निगम को इस पर नियम के तहत काम करने के लिए कहा है। वकील भट्ट ने कहा कि महामारी के दौरान बेदखल किए जाने वाले लोगों के लिए कम से कम एक अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं हैं।

12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला वापस नहीं होगा और इसके साथ ही सीआईएससीई और सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को मंजूरी दे दी जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमश- 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा।

काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस (सीआईएससीई) ने हालांकि कहा कि वह विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए पिछले छह कक्षाओं के प्रदर्शन पर विचार कर रहा है जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 12वीं के विद्यार्थियों के अंतिम नतीजों को तैयार करने के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रदर्शन को आधार बनाने का प्रस्ताव किया है। दोनों बोर्ड ने कहा कि वे 31 जुलाई या उससे पहले नतीजे घोषित करेंगे। सीबीएसई ने अदालत को अपनी मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 12वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन में 30 प्रतिशत अंक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के आधार पर, 30 प्रतिशत 11वीं कक्षा के अंक के आधार पर और 40 प्रतिशत अंक 12वीं कक्षा की छमाही परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।

सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक आधार पर प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में मिले अंक जिसे स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया गया है उसपर भी अंतिम नतीजे तैयार करते वक्त गौर किया जाएगा। न्यायमूर्ति एएम

खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की विशेष अवकाश पीठ ने इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि सीबीएसई और सीआईएससीई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। सिंह का तर्क था कि समान विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) पारंपरिक तरीके से कराया जाएगा।

पीठ ने कहा कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले को आगे नहीं ले जाया जाना चाहिए। हमने पहले ही सैद्धांतिक रूप बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले को स्वीकार किया है और जिसे हमारे सामने रखा गया था। वैसे भी जो विद्यार्थी अंकों में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं यह व्यस्था ऐसे विद्यार्थियों का ख्याल रखती है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनको लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगी। वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टाया मूल्यांकन योजना को स्वीकार करने को लेकर कोई आशंका नहीं है और बोर्ड इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पीठ ने सीबीएसई की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सीआईएससीई का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जेके दास से कहा कि हालांकि, (मूल्यांकन) योजना में विवाद समाधान का प्रवाधान उस स्थिति में होना चाहिए अगर विद्यार्थी अंतिम नतीजे में सुधार चाहते हैं और दूसरा नतीजे घोषित होने और वैकल्पिक परीक्षा के लिए समय सारिणी जारी होती है। दोनों बोर्ड ने पीठ के सुझाव पर सहमति जताई और इस मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है, उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह मूल्यांकन योजना पर अपना पक्ष रखेंगे।

पीठ ने कहा कि हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे। आप (सीआईएससीई और सीबीएसई) अपनी योजना को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने को स्वतंत्र हैं। अगर कोई सुझाव आता है तो हम उसपर विचार कर सकते है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि सिंह के सुझाव को बाद में शामिल किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

विभिन्न राज्यों द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर कुछ अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि आवेदन की प्रति राज्य सरकारों के लिए वकीलों को दिया जाए।

टीबी रोकथाम के लिए उपचार को बढ़ावा गेम चेंजर साबित होगा : हर्षवर्धन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि टीबी रोकथाम के लिए उपचार को बढ़ावा देना गेम चेंजर साबित हो सकता है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक पांच करोड़ मरीजों को उपचार दिया जा चुका है। सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है जिसे लेकर लगातार प्रयास जारी हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने टीबी रोकथाम के प्रयासों में तेजी लाने के वैश्विक अभियान संबंधित बैठक में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, पिछले एक वर्ष में कोविड संकट के बावजूद हमने नुकसान की तेजी से भरपाई करने और टीबी मरीजों को लगातार सेवाएं जारी रखने के लिए अधिक स्फूर्ति और लचीलेपन से काम किया है। बाईडायरेक्शनल स्क्रीनिंग, सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाने के काम को कोविड-19 की निगरानी के साथ जोड़ते हुए टीबी रोगियों की पहचान की। साथ ही इन मरीजों के घर तक सेवाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले को साल 2020 में देश का पहला टीबी मुक्त केंद्र और जिला घोषित किया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में और राज्य व जिले टीबी मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, कोविड के अनुभव से सीख लेकर हम पांच-टी कार्यनीति पर आधारित टीबी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं।

कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार

» जिला स्तर पर तैयार की जा रही है कार्ययोजना

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज़िले के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में कार्ययोजना बनाकर 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्वास्थ्य अधोसरंचना को सशक्त बनाने और छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाक़ों तक सर्वसुविधायुक्त उपचार व्यवस्था बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए अनुभवों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलाचिकित्सालयों एवं विकासखण्ड स्तरीय अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है। बघेल ने कहा है कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती देने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाना है, ताकि यदि तीसरी लहर की स्थिति बनती भी है तो उससे पूरी ताकत के साथ निपटा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 6 माह में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन अस्पतालों में आक्सीजन संबंधी उपकरण आई.सी.यू. बिस्तर, वेन्टिलेटर्स इत्यादि की संख्या में वृद्धि हुई है। इन स्वास्थ्य उपकरणों का बेहतर रखरखाव और लगातार उपयोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की संख्या में भी पिछले दिनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, किन्तु स्वास्थ्य प्रबंधन और मजबूत किया जाना आवश्यक है। बघेल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास की एक योजना शीघ्र तैयार की जाये।

कोरोना से दैनिक मौतों में आई गिरावट, 24 घंटे में 2330 की मौत, 67208 नए केस

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले दो दिन से कोरोना वायरस के दैनिक मामलो में मामूली ही सही, लेकिन बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है। वहीं देश में पिछले 71 दिनों बाद सक्रीय मामलों की संख्या सबसे कम देखी गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 67208 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,97,00,313 पर पहुंच गई। जबकि कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2,330 लोगों की जान चली गई। इस प्रकार देश में कोरोना से अपनी जवान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 3,81,903 हो गई है। वहीं अस्पतालों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की संख्या

कम होकर 8,26,740 रह गई है, जो महामारी का इलाज करा रहे मरीजों की 71 दिनों बाद सबसे कम संख्या है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 8,26,740 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.78 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से उबरने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 95.93 फीसदी है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में 38,692 की कमी आई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण की दैनिक दर 3.48 प्रतिशत दर्ज की गई। यह लगातार 10 दिनों में पांच प्रतिशत से कम बनी हुई है। साप्ताहिक संक्रमण दर कम होकर 3.99 प्रतिशत रह गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 35वें दिन संक्रमण के दैनिक मामलों से अधिक है। अब तक कुल 2,84,91,670 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.29 प्रतिशत हो गई है।

❐ **महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें-** मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में जिन 2,330 लोगों की मौत हुई है, उनमें सर्वाधिक 1,236 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। जबकि 270 की तमिलनाडु, 148 की कर्नाटक और 147 लोगों की मौत केरल में हुई। देश में इस महामारी से अब तक 3,81,903 लोगों की मौत हो चुकी है।इनमें से 1,15,390 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 33,296 की कर्नाटक, 30,338 की तमिलनाडु, 24,876 की दिल्ली, 21,963 की उत्तर प्रदेश, 17,118 की पश्चिम बंगाल, 15,698 की पंजाब और 13,354 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई।

आधुनिक होंगी देश की 41 आयुध फैक्टरियां, केंद्र ने दी 7 कंपनियों में बदलाव को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाते हुए बुधवार को करीब 200 साल पुराने आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार करना है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और असलहा तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्टरियों को आपस में विलय करते हुए सात कंपनियों में तब्दील किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने करीब दो दशकों से लंबित इस सुधार प्रक्रिया पर मंजूरी देकर मुहर लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इन आयुध कारखानों में कार्यरत 70,000 कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी के मकसद से लिया गया है। यह एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा जरूरतों को पूरी की जा सकेंगी। इससे हमें अपने रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, सभी सात कंपनियां रक्षा क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी और उनका संचालन पेशेवर प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिनका लक्ष्य उत्पादों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किफायती और बेहतरीन गुणवत्ता देना होगा।

लखनऊ में नौचंदी एक्सप्रेस के दो पहिये पटरी से उतरे, ढाई घंटे तक अटकी रहीं यात्रियों की सांसें, कई ट्रेनें लेट

लखनऊ (आरएनएस)। प्रयागराज से लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस बीती रात 10.10 बजे केकेसी पुल के पास डिरेल हो गई। उसके इंजन के दो पहिए पटरी से उतर गए। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और क्रेन के जरिए इंजन के दोनों पहियों को पटरी पर किया गया। इस वजह से ट्रेन करीब ढाई घंटे देरी से करीब एक बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचकर मेरठ सिटी के लिए रवाना हुई। प्रयागराज से मेरठ सिटी के आने वाली सभी ट्रेनें करीब ढाई घंटे तक प्रभावित रही।

डीरेलमेंट की सूचना मिलते ही चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन अलर्ट

हो गया और स्टेशन डायरेक्टर सुदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया गया।

❐ **गनीमत रही ट्रेन की स्पीड रही कम-** गाड़ी संख्या 04511 प्रयागघाट संगम से मेरठ सिटी को जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस बुधवार रात 10.10 बजे दिलकुशा से चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान ट्रेन की स्पीड कम थी। केकेसी पुल के पास पहुंचने पर ट्रेन के इंजन के दो पहिए डीरेल हो गए। इससे तेज आवाज हुई और ट्रेन में जोर का झटका लगा। बोगी में बैठे कई यात्री अपनी सीट से नीचे गिर गए। हालांकि, यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं।

❐ **क्या पटरी में कोई कमी तो नहीं थी, होगी जांच-** नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के दो पहिए कैसे उतरे इसकी जांच होगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि जांच में यह देखा जाएगा कि किसकी गलती है। क्या ट्रैक में तो कोई खराबी तो नहीं थी। क्या कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे। क्या पटरी में कोई कमी तो नहीं थी। फिलहाल डीरेलमेंट की वजह की जांच में इन्हीं बिंदुओं को टटोला जाएगा।

❐ **तेज झटका और ट्रेन रुक गई-** नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के दो पहिए पटरी से उतरने के बाद ट्रेन करीब ढाई घंटे तक उसी जगह पर खड़ी रही। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लखनऊ के लिए प्रयागराज से निकले राम प्रवेश ने बताया कि ट्रेन की स्पीड मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की रही होगी। इतने में केकेसी पुल के पास तेज आवाज हुई और जोर से झटका लगा और ट्रेन रुक गई।

जोरदार झटके और आवाज से लोग सहम से गए। कई यात्रियों को हल्की चोट भी आई। जब काफी देर से ट्रेन नहीं चली तो लोग उतरकर कारण जानना चाहे तो पता चला कि इंजन के दो पहिए उतर गए हैं। लोग यही कह रहे थे कि गनीमत रही ट्रेन की स्पीड कम थी वरना आज पता नहीं क्या होता।

❐ **डीआरएम बोले-जांच कराई जाएगी-** नार्दन रेलवे के डीआरएम संजय त्रिपाठी का कहना है कि ट्रेन के डीरेल होने के मामले की जांच कराई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षा शाखा की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी आखिर कैसे ये ट्रेन पटरी से उतर गई।